भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 2476

जिसका उत्तर 05.03.2020 को दिया जाना है

आर.यू.बी. का निर्माण

2476. श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डीः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का बड़े जंक्शनों जैसे कि मुडिरेड्डी पल्ले, राजापुर मंडल, पेड्डायपल्ले, बाला नगर जेडचेरला क्षेत्र के मनादाले, कानीमेट्टा, कोथा कोटा मनाडल और देवेरकाडरा क्षेत्र के बेमुला में कोथुर से कुरनूल तक राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर सड़क अधेगामी पुल (आर॰यू॰बी) के निर्माण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में तेलंगाना सहित सड़क सुरक्षा के लिए बैठक आयोजित करने की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या हाल ही में तेलंगाना के हैदराबाद या महबूबनगर में ऐसी बैठक आयोजित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) मुडिरेड्डी पल्ले, राजापुर मंडल में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने स्थल की परिस्थितियों के अनुसार सड़क पुल के नीचे (आरयूबी) के स्थान पर सर्विस रोड के निर्माण का निर्णय लिया। यह कार्य 31.03.2021 तक पूरा कर लिया जाना निर्धारित है। जेडचेरला क्षेत्र के पेडडेपल्ले बालानगर मंडल और देवेरकाडरा क्षेत्र के बेमुला के संबंध में, दीर्घकालिक सुधार के लिए अध्ययन शुरू कर दिया गया है और सुधार के उपाय 31.12.2022 तक पूरा होने के लिए निर्धारित हैं। इसके अलावा, कानीमेट्टा, कोथाकोटा मंडल ब्लैकस्पॉट स्थान पर सड़क सुरक्षा कार्य 30.05.2020 तक पूरा कर लिया जाना निर्धारित है।

(ग) और (घ) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सितंबर, 2017 में माननीय संसद सदस्य (लोकसभा) के नेतृत्व में प्रत्येक जिले में एक सड़क सुरक्षा समिति को अधिसूचित किया है। जिले में निवास करने वाले संसद के माननीय सदस्य (आरएस) समिति, जिसे पुनर्नामित कर "सड़क सुरक्षा के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र समिति" किया गया था, के एक विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। इसके बाद, समिति को 19 दिसंबर, 2019 की अधिसूचना के अनुसार "संसद की सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य" के रूप में नया नाम दिया गया है। जिला कलेक्टर समिति के सदस्य सचिव हैं और जिला स्तर पर अन्य संबंधित विभाग समिति के सदस्य हैं। समिति को कम से कम तीन महीने में एक बार या ऐसी आवृत्ति जैसा कि वह तय करे, पर मिलना होता है। मंत्रालय जिला सड़क सुरक्षा समिति और संसद की सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों का विवरण नहीं रखता है।

*****